

the Chief Minister of Madhya Pradesh is a matter of great indignation and shame.

If custodians of law and order commit such heinous crimes and get away with it then criminals can easily have a free hand.

It has been alleged that many women were detained for 18 days at the police camp and even 'paraded naked' in a nearby village. If this is true, then the suspicion that there is a presence of some criminals in the police force gets credence.

The attitude of the Police high ups was exposed when the Police Commissioner of Delhi justified the treatment of Maya Tyagi on the ground that dacoits deserved no better treatment. If the highest authority in the Police Department holds such views then there is no wonder that the Constables and persons in lower rank can behave in any manner they feel like.

Failure on the part of the Government to take action against Police, as has happened in the case of Maya Tyagi or housewives of textile workers at Modinagar, would lead to the feeling among Police that the Government was willing to connivance at Police atrocities against women.

I request the Government to take immediate and firm action against the guilty ones so that it may act as a deterrent in future.

(x) ALLEGED UN-HYGIENIC CONDITIONS PREVAILING AT SHEIKHPURA RAILWAY STATION IN BIHAR.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) :
उपाध्यक्ष महोदय, शेखपुरा रेलवे स्टेशन, जिला मुंगेर बिहार बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जहां विश्राम घर है वहीं पर एक खुला हुआ शौचालय है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बीमारी का घर है। गंदगी का

अंबार चारों ओर लगा रहता है। सारे समय यात्रियों को मल-मूत्र के बीच ही रहना पड़ता है। शेखपुरा मुंगेर जिला में एक महत्वपूर्ण स्थान है। रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूँ कि द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय स्थित शौचालय को अन्यत्र हटाया जाए एवं साथ ही साथ स्टेशन के बाहर की गंदगी को समाप्त करने के लिए बाउंड्री वाल (दीवाल) का निर्माण किया जाए। नहीं तो सैकड़ों लोगों को महामारी का शिकार होना पड़ेगा।

(xi) STEPS TO IMPROVE THE LOT OF BEGGARS BY PROVIDING THEM WITH JOBS.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के 33 वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी आज भी देश के लाखों व्यक्ति भिक्षावृत्ति पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉपों और बड़े तथा छोटे शहरों में उनकी संख्या को देखकर प्रत्येक व्यक्ति आतंकित हो जाता है। जब भी हम किसी विदेशी पर्यटक को चिबड़ों में लिपटे भारतीय भिक्षारियों से घिरा देखते हैं तभी हमारी 34 वर्षों के तथाकथित सामाजिक तथा आर्थिक विकास की वास्तविकता नग्न रूप में सामने आ जाती है और हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।

सरकार को चाहिए कि वह इन लाखों व्यक्तियों को, जिन्होंने भिक्षावृत्ति को अपनाया है, सहायता प्रदान करे, ताकि ये लोग सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें और देश के अर्थे नागरिक बन सकें। भिक्षा की विभीषिका को समाप्त करने के उपाय किए जाने चाहिए। जब तक सरकार इस जन-शक्ति को उद्योगों तथा अन्य व्यवसायों में नियोजित करने की एक निश्चित